

नोटिस : अपेक्षाएँ और औचित्य

1) Notice/Information/ Knowledge:

नोटिस शब्द मूलतः लैटिन भाषा के शब्द 'notifia' से लिया गया है। किसी भी प्रशासनिक/अर्द्धन्यायिक/न्यायिक प्रक्रिया का प्रारम्भ नोटिस से ही होता है इसलिए नोटिस शब्द को न्यायिक निर्णयों में किस प्रकार लिया जाना यह हम सब के लिए आवश्यक है। नोटिस शब्द का अत्यन्त महत्व है। क्योंकि किसी भी अधिनियम में कार्यवाही के प्रारम्भ करने के लिए सामान्यतः नोटिस देने का उल्लेख किया जाता है और नोटिस संबंधित व्यक्ति को उसी रीति से दिया जाना अपरिहार्य है। अन्यथा यह मानने का समुचित विधिक आधार होगा कि कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना संबंधित व्यक्ति को निर्धारित रीति से, निर्धारित अवधि में नहीं दी गयी। नोटिस का अभिप्राय अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के क्षेत्र के अन्तर्गत ही विचारित किया जाना चाहिए।

“**Notice**” and “**Intimation**” The term notice connotes something more concrete than a mere disclosure or intimation. In the background of a serious impact on valuable rights of parties the term 'notice' has been associated with direct, specific and definite intimation *effectively* given. (1986 Ker LJ 43 (SM 70) [Cooperative Societies Rules 1969 (Kerala Rule 35 (3) (a)].

Notice ? : Dictionary Meanings

- 1) **THE RANDOM HOUSE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE - Edition 1983 – Page 986 : Notice – 1. Information or Intelligence, 2. An intimation.**
- 2) **NEW WEBSTER'S DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE – Edition 1981 – Page 649: Notice – 1. The act of noting, observing or remarking.**
- 3) **THE CHAMBERS DICTIONARY, Edition 2002 – page 1107: Notice – 1. Intimation, 2. Announcement, 3. Warning**

2) नोटिस : वास्तविक विधिक आशय

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषतः विधि के क्षेत्र में सरकारी विभाग से प्राप्त नोटिस, किसी प्रक्रिया का प्रारम्भिक चरण होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु है। अतः उसका सूक्ष्म विश्लेषण और सम्यक अध्ययन इस दृष्टि से किया जाना चाहिये कि -

- * क्या उस पर जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मोहर आदि अंकित है और यदि उसे निर्धारित प्रोफार्मा में जारी किया जाना चाहिये तो वह तदनुसार है ?
- * क्या उसमें प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में समुचित तथ्य अंकित हैं ?
- * क्या उसकी तामीली अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उचित और विधिक है ?
- * क्या नोटिस में निर्धारित तिथि और उसे प्राप्त करने की तिथि के बीच उत्तर प्रस्तुत करने के लिये उचित समय दिया गया है ?

यह दोनो पक्षों के लिये, आगे की कार्यवाही के लिये मजबूत विधिक आधार प्रदान करता है।

3) नोटिस : मूल विधिक अपेक्षा

नोटिस का आशय केवल स्थान/दिनांक/समय से अवगत कराना नहीं होना चाहिये यद्यपि लगभग शत-प्रतिशत नोटिस विभाग में प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक केवल सूचना मात्र देते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं।

नोटिस किस प्रकार का होना चाहिये इसे माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने *Burhanuddin Hussain vs . State Of Andhra Pradesh And Ors. [AIR 1970 AP 137]* के वाद में इस प्रकार व्यक्त किया :-

when a quasi judicial body embarks on determining disputes between parties must adhere to the rule *Audo Alterum Partem*, which says no one should be

condemned unheard. Notice is the limb of this rule, **it must be precise and unambiguous, it must apprise the party determinatively the a case he has to meet**, adequate time to his representation must be given, in the absence of the notice of the kind and such reasonable opportunity the order passed against the person absinthial becomes wholly vitiated .

P. Ramanathan Iyer की The Major Law Lexicon (2010 Edition) Page 4634 में नोटिस की 51 श्रेणी अंकित है।

अनेक अधिनियमों के अन्तर्गत नोटिस शब्द परिभाषित है या न्यायालयों द्वारा परिभाषित किया गया। उनमें से दो परिभाषायें उल्लेखनीय हैं -

“The legal instrumentally by which knowledge is conveyed, or by which one is charged with knowledge.”

The term “*notice*” in its full legal sense embraces a knowledge of circumstances that ought to induce suspicion or belief, as well as direct information of the fact.

उक्त कसौटी पर प्रत्येक नोटिस को परखना चाहिये और यदि उसमें केवल निष्कर्ष हैं और ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने के कारण और आधार का उल्लेख नहीं है तो ऐसे नोटिस विधि के कसौटी पर खरे नहीं उतरते। यह उल्लेखनीय है कि विधि के प्रत्येक क्षेत्र में जिसमें वाणिज्य कर भी सम्मिलित है किसी परवर्ती कार्यवाही की वैधता नोटिस के वैध रूप से तामील कराने पर निर्भर करती है अतः नोटिस की तामिली की वैधता भी उसका एक अत्यावश्यक अंग है।

4) नोटिस न दिया जाना: अधिनियम में उल्लेख न होने पर:

यदि किसी अधिनियम में यह व्यवस्था नहीं है तो भी नोटिस का देना संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत आवश्यक है। **Maneka Gandhi vs Union Of India on 25 January, 1978 Equivalent citations: 1978 AIR 597, 1978 SCR (2) 621** उक्त वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने मानेका गांधी के पासपोर्ट को बिना नोटिस, जब्त किये जाने पर विस्तार से विवेचना की। क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम में जनहित में

पासपोर्ट जब्त किये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने यह सूचित करने से मना किया कि जनहित के किस कारण से उक्त पासपोर्ट जब्त किया गया। रिट याचिका में प्रथम प्रश्न यह उठाया गया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(C) में नोटिस न दिये जाने के उल्लेख में भी उन्हें नोटिस न दिया जाना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है तथा अनुच्छेद 19(1)(A) का भी उल्लंघन है एवं अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है।

किन्तु उक्त रिट याचिका में उक्त पीठ द्वारा बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के अनुसार व्यक्ति को सुने बिना उसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

The principle of *audi alteram partem*, which mandates that no one shall be condemned unheard, part of the rules of natural justice. In fact, there are two main principles in which the rules of natural justice are manifested, namely, *Nemo Judex in Sua Causa and audi alteram partem*. We are not concerned here with the former, since there is no case of bias urged here. The question is only in regard to the right of hearing which involves the *audi alteram partem* rule. Can it be imported in the procedure for impounding a passport ?

5) नोटिस में उल्लिखित आरोप से संबंधित साक्ष्य की प्रतियाँ आवश्यक:-

सामान्य रूप से विभाग से जो नोटिस प्राप्त होते हैं उसमें वे साक्ष्य संलग्न नहीं होते जिनके आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित होती है इस तथ्य को साक्ष्य से समर्थित किये बिना आमतौर पर नोटिस जारी करने की प्रथा है। नोटिस में क्या आवश्यक है?

माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित के वाद में यह उल्लिखित किया कि

- 1- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Raj Kishore Jha Vs. State of Bihar* [2003, 11 SCC 519] में यह व्यवस्था दी कि :-

Reason is the heart beat of every conclusion. It introduces clarity in an order and without the same it becomes lifeless.

इस निवेदन को Lord Denning, M.R. द्वारा *Breen Vs. Amalgamated Engg. Union* [1971] 1 All ER 1148, के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना उचित होगा। “The giving of reasons is one of the fundamentals of good administration.” In *Alexander Machinery (Dublely) Ltd. Vs. Crabtree* (1974) ICR 120 (NIRC) it was observed :

“Failure to give reasons amounts to denial of justice”. “Reasons are live links between the mind of the decision-taker to the controversy in question and the decision or conclusion arrived at. “Reasons substitute subjectivity by objectivity. The emphasis on recording reasons is that if the decision reveals the “inscrutable face of the sphinx”, it can, by its silence, render it virtually impossible for the courts to perform their appellate function or exercise the power of judicial review in adjudging the validity of the decision. Right to reason is an indispensable part of a sound judicial system; reasons at least sufficient to indicate an application of mind to the matter before court. Another rationale is that the affected party can know why the decision has gone against him. One of the salutary requirements of natural justice is spelling out reasons for the order made; in other words, a speaking-out. The ‘inscrutable face of the sphinx’ is ordinarily incongruous with a judicial or quasi-judicial performance.

2- नोटिस में आरोप से संबंधित साक्ष्य प्रदान किया जाना अपरिहार्य

मद्रास उच्च न्यायालय ने सर्वश्री **Rajam Industries (P) Ltd. vs. The Deputy Commercial Tax Officer [2010 (178) ECR 0095]**

Nevertheless, the Petitioner is entitled to have copies of those statements obtained during preliminary investigation to enable it to give proper explanation to the Show Cause Notice.

The basic principle is that a show cause must be a real show cause, keeping an open mind with regard to the subject matter of the enquiry proposed that if the show cause bears out a foreclosed or a prejudged mind that will violate the principles of natural justice.

A Show Cause Notice, as it was held by a Division Bench of this Court presided over by Nainar Sundaram J. (as His Lordship then was), is the basis and it must be impartial and its fairness and impartiality can be culled out. On the facts and circumstances of the present case the first Respondent, on being prima facie satisfied with the facts, and after making factual assertions, has chosen to give the Show Cause Notice. In the Show Cause Notice, the first Respondent should have explained about the facts and asked the other side to give explanation and should not have arrived at a conclusion that the other side has committed a mistake, in which event. The explanation will be an empty formality only.

3- सर्वश्री **Burhanuddin Hussin Vs. State Of Andhra Pradesh And Ors [AIR 1970**

AP 137] के वाद में दिये गये निर्णय के इस अंश से कि नोटिस से क्या अभिप्राय है वर्तमान नोटिस को परखा जाना उचित होगा कि **it must be precise and**

unambiguous, it must apprise the party determinatively the a case he has to meet.

6) नोटिस में दी गयी सूचना अपूर्ण या असत्य होने पर:-

उक्त परिस्थितियों में नोटिस की वैधता बनी रहेगी यदि वह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत जारी किया गया है किन्तु अपूर्णता के संबंध में अधिवक्ता महोदय संबंधित अधिकारी को यह सूचित करें कि नोटिस में क्या अपूर्णता है।

7) नोटिस लिखित होना चाहिए:-

The word 'notice' denotes merely an intimation to the party concerned of a particular fact. It cannot be limited to a letter. Notice may take several forms. It must, to be sufficient, be in writing and must intimate quite clearly that the award has been made and signed. *Parasramka Commercial Co. Ltd. v. Union of India*, AIR 1970 SC 1654, 1656. [Arbitration Act (10 of 1940), S. 14(1)].

Parasramka Commercial Co. Ltd. v. Union of India, AIR 1970 SC 1654, 1656. [Arbitration Act (10 of 1940), S. 14(1)].

8) Reason : Conclusion

अधिकांशतः नोटिस में निष्कर्ष (Conclusion) दिये जाते हैं और उन कारणों का उल्लेख नहीं होता है या भलीभाँति नहीं होता अर्थात् नोटिस देने वाला अधिकारी किन कारणों के आधार पर नोटिस में दिये जाने वाले निष्कर्ष पर पहुँचा, यह नोटिस से विदित नहीं होता फलतः ऐसे नोटिस प्राणरहित देह के समान निष्प्रयोज्य होते हैं। फलतः नोटिस का जवाब दिये जाने के पूर्व कारण या कारणों के उल्लेख के अभाव में स्वतः प्रेरित उत्तर प्रस्तुत किये जाने से, यदि उत्तर पूर्ण नहीं है तो हम पहल खो देते हैं और नोटिस जारी करने वाले के विवेकाधीन हो जाते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में *M/s. Real Estate Agencies vs. Govt. of Goa and Others* [AIR 2012 S.C. 3848] के वाद में इस संबंध निम्नलिखित मत व्यक्त किया :-

7- Time and again this court has emphasized that such course of action by a court cannot lead to a legally accepted conclusion inasmuch as the manner of reaching the decision and reason there for are sacrosanct to the judicial process.

पूर्व में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने reason and conclusion, के अन्तर को *Steel Authority of India Versus Sales Tax Officer, Rourkela [2008 (44) STJ - 547]* (*Supreme Court*) (decided on 10-07-2008) के वाद में अत्यन्त स्पष्टता के साथ, अपने पूर्व निर्णय में *Raj Kishore Jha Vs. State of Bihar [2003, 11 SCC 519]* को उद्धरित किया और उसकी पुष्टि की :-

निम्नलिखित पंक्तियाँ भी विचारणीय हैं :-

Lord Denning, M.R. in *Breen Vs. Amalgamated Engg. Union [1971] 1 All ER 1148*, held **“The giving of reasons is one of the fundamentals of good administration.”** In *Alexander Machinery (Dublely) Ltd. Vs. Crabtree (1974) ICR 120 (NIRC)* it was observed : **“Failure to give reasons amounts to denial of justice”**. **“Reasons are live links between the mind of the decision -taker to the controversy in question and the decision or conclusion arrived at. “Reasons substitute subjectivity by objectivity. The emphasis on recording reasons is that if the decision reveals the “inscrutable face of the sphinx”, it can, by its silence, render it virtually impossible for the courts to perform their appellate function or exercise the power of judicial review in adjudging the validity of the decision. Right to reason is an indispensable part of a sound judicial system; reasons at least sufficient to indicate an application of mind to the matter before court. Another rationale is that the affected party can know why the decision has gone against him. One of the salutary requirements of natural justice is spelling out reasons for the order made; in other words, a speaking-out. The ‘inscrutable face of the sphinx’ is ordinarily incongruous with a judicial or quasi-judicial performance.**

अतः नोटिस जारी करने वाले अधिकारी और नोटिस पाने वाले व्यापारी या संबंधित पक्ष को उक्त निर्णयों के आलोक में नोटिस की सम्यक विवेचना इस दृष्टि से करनी चाहिये कि क्या वह वास्तव में अपेक्षाओं के अनुरूप है और यदि तो इस संबंध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

:: GST में नोटिस/आदेश आदि की सर्विस ::

जी०एस०टी० एक्ट 2017 में अधिकांशतः कार्य कामन पोर्टल के माध्यम से होते हैं इसकी परिभाषा धारा 146 उद्धरित है :-

सामान्य पोर्टल-

सरकार, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण प्रसुविधा, कर के सामान्य संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण एकीकृत कर की संगणना और निपटान, इलेक्ट्रानिक वे बिल को सुकर बनाने के लिये और ऐसे अन्य कृत्यों के क्रियान्वयन के लिये और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो विहित किये जायें के लिये सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।

न्यायिक निर्णय -

सर्वश्री Pee Bee Eterprises versus Assistant Commissioner SGST and others. Writ Petition (C) No. 14376 of 2020, Kerala High Court, decided on 17-08-2020
के वाद में एकल पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया :-

“I find from a reading of the statement of the respondent that the assessment orders dated 20.8.2019 were served on the petitioner through publication on the web portal on 20.8.2019 itself. Over and above that, an email was also sent to the petitioner at his registered email id, although the petitioner says that he did not receive the email but received only a copy of the or through registered post much later. I find however, that the service of an order through the web portal is one of the methods of service statutorily prescribed under Section 161(1)(c) and (d) of the SGST Act. If that be so, then the petitioner cannot deny the fact of receipt of the order on 28.9.2019 for the purposes of filing the returns as contemplated under Section 62 of the SGST Act with a view to getting the assessment order withdrawn. In as much as the return filed by the petitioner for the period April and May 2019 was only on 30.10.2019,ie., 71 days after the date of service of the assessment order through the web portal (20.8.2019), the petitioner cannot aspire to get the benefit of withdrawal o f the assessment orders contemplated under Section 62 of the SGST Act.

यह सिद्ध करने का भार दायित्व करदाता का है कि उसे कॉमन-पोर्टल या ई-मेल द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः उसे अपने अधिकारी के माध्यम से अधिकारी को इस आशय की सूचना देते हुए नोटिस/आदेश/अन्य विषयक की मॉग की जानी चाहिए।
